और विनियमन) अधिनियम ; 1986 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन नहीं कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं ;

(घ) उपरोक्त अधिनियम का सभी राज्यों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 को ज्यादा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करें । ऊत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों, इनमें से प्रत्येक राज्य में लगभग एक मिलियन या इससे ज्यादा कामकाजी बालक हैं, ने सफल अभियोजनों की निश्चित संख्या की रिपोर्ट नहीं दी है । कम बाल श्रमिक वाले अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है । इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र ने पिछले दो वर्षों से कोई सूचना नहीं दी है और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र "शून्य" कार्रवाई की सूचना देते रहे हैं ।

(ग) से (ङ) राज्य सरकारों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं । पिछले श्रम मंत्री सम्मेलन में इस मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ था । राष्ट्रीय एवं राज्य के संस्थानों के माध्यम से प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

गुजरात के कृषि श्रमिकों के लिये कल्याण योजनाएं

1943. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के कृषि श्रमिकों के लिये सरकार स्वीकृत कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं से कृषि श्रमिकों को अब तक कितना लाभ हुआ है ;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् जिला स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई और कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है व सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक एककों का बन्द होना

1944. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और वे कहां पर स्थित हैं जो बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) ये एकक कब से बन्द पड़े हैं अथवा बन्द होने के कगार पर हैं और इनके बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार इन एककों को पुर्नजीवित करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ;

(घ) इन एककों के बन्द होने के परिणामस्वरूप रोजगार से वंचित होने वाले कर्मचारियों और कामगारों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या इन एककों के कामगारों को राष्ट्रीय राजस्व निधि से कोई राहत प्रदान की जाती है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों के नाम

1945. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मान्यता प्राप्त श्रमिकों संघों के नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1992-93 में ऐसे प्रत्येक श्रमिक संघ की कुल सदस्यता संख्या कितनी थी ; और

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल सदस्यता संख्या कम होने की वजह से किसी श्रमिक संघ को मान्यता रद्द की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) 31-12-1980 की गणना की तारीख मानकर आयोजित पिछले सामान्य सत्यापन के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, समितियों, परिषदों, वेतन बोर्डों आदि में निम्नलिखित केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार उनकी सत्यापित सदस्यता उनके नामों के सामने दी गयी है :—

क्रम सं०	केन्द्रीय संगठन का नाम	31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सत्यापित सदस्यता
1.	आई एन टी यू सी	22,36,128
2.	बी एम एस	12,11,345
3.	एच एम एस	6,62,882
4.	यू टी यू सी (एल एस)	6,21,359
5.	एन एल ओ	2,46,540
6.	यू टी यू सी	1,65,614
7.	टी यू सी सी	1,23,048
8.	एन एफ आई टी यू	84,123
9.	ए आई टी यू सी	3,44,746
10.	सी आई टी यू	3,31,031
	कुल :	61,26,816

31-12-1989 को गणना की तारीख मानकर केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की सदस्यता का निर्धारण करने के लिये सामान्य सत्यापन कार्य शुरू किया जा चुका है और सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।

चूंकि किसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठन को मान्यता प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है अतः मान्यता को रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

Generation of Employment

1946. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) the thrust/strategy adopted during the Eighth Five Year Plan for the generation of employment; and.